वैज्ञानिक कथाकार नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन और चुनाव आयोग का समापन

रवीश कुमार

अगस्त 2008 की एक सुबह हम चेन्नई से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुँचे थे। दुनिया भर से आए दर्जनो अंतरिक्ष-पत्रकारों के बीच मैं गाँव गली कवर करने वाला भी पहुँच गया था। भारत अपना पहला मून मिशन चंद्रयान का प्रक्षेपण करने वाला था। वहाँ दुनिया भर से आए ऐसे पत्रकार थे जो कई वर्षों से अंतरिक्ष प्रक्षेपण कवर कर रहे थे। यही उनका कार्यक्षेत्र भी था। वे भारत की कामयाबी को शक और हैरत से देख रहे थे। भारत की तरफ से दो चार ही अनुभवी पत्रकार थे। बाकी फ़ोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे।

बहरहाल बारिश की बूँदें कुछ सेकेंड के लिए रूकी और उतनी ही देर में चंद्रयान अपने लक्ष्य की तरफ निकल गया। वह क्षण देखना और दर्शकों को दिखाना दोनों ही गर्व का था। उसके बाद हम सभी छत से उतर कर एक बड़े से सभागार में लाए गए, जहाँ चंद्रयान प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने हम सबको बताया। उस समय इसरो के प्रमुख जी माधवन थे। सैंकड़ों कैमरे के सामने देश के वैज्ञानिक देश से बात कर रहे थे। उसके बाद के कुछ दिनों तक वही वैज्ञानिक कई न्यूज़ चैनलों में जाकर अपनी कामयाबी के बारे में बता रहे थे।

2008 की कामयाबी मामूली नहीं थी। तब भी भारत में एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम मनमोहन सिंह था।उन्होंने बधाई दी और बाकी वैज्ञानिकों पर छोड़ दिया कि वे देश से संवाद करें। सैंकड़ों कैमरों के सामने इसरो के वैज्ञानिक थे। मनमोहन सिंह और उनसे पहले के किसी प्रधानमंत्री ने इसरो की कामयाबी को अपने चुनावी पोस्टर में इस्तमाल नहीं किया। बुधवार को मिशन शक्ति के सफल होते ही व्हाट्स एप यूनिवर्सिटी में मिसाइल की फ़ोटो के साथ नरेंद्र मोदी के पोस्टर बनकर चलने लगे थे।

यही नहीं 28 मार्च को जब भारत ने ए-सैट मिसाइल क्षमता का परीक्षण किया तो कैमरों के सामने से सारे वैज्ञानिक ग़ायब कर दिए गए। सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने थे। इस कामयाबी की एक ही तस्वीर जनता के बीच पहुँची है। राष्ट्र के नाम संबोधन वाली नरेंद्र मोदी की तस्वीर। उनके सहयोगी इसे फ़ैसला लेने वाली सरकार की कामयाबी बताते रहे। प्रक्षेपण और परीक्षण के समय जश्न मनाते वैज्ञानिकों की तस्वीरें भी नज़र नहीं आईं।

एनडीटवी के आर्काइव में - 19 अप्रैल 2012 का एक वीडियो फुटेज है। उस समय भारत ने लो-ऑरबिट में उपग्रह को मारने वाली मिसाइल अग्नि-V का सफल परीक्षण किया था। वीडियो में तब के डीआरडीओ के निदेशक जश्न मनाते दिख रहे हैं। 28 मार्च 2019 को भी डीआरडीओके निदेशक पद पर डॉ जी सतीश रेड्डी विराजमान हैं मगर वे मीडिया से ग़ायब थे। उनकी टीम ग़ायब थी। उनकी जगह डीआरडीओ से रिटायर और इस समय नीति आयोग के सदस्य बन चुके विजय सारस्वत मीडिया में इसके बारे में ज्ञान दे रहे थे। मौजूदा चेयरमैन और वैज्ञानिक देश के सामने से ग़ायब रहे। एक रिटायर किया हुआ चेयरमैन ज्ञान दे रहा था ताकि वह इसी बहाने यूपीए सरकार पर टिप्पणी कर सके कि उसने मिशन शक्ति की अनुमति नहीं दी। बाद में इन्हीं के बयान के सहारे अरुण जेटली बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। मौजूदा चेयरमैन यह बात नहीं कह सकते थे क्योंकि चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है।

जबकि इसी वी के सारस्वत ने 10 फ़रवरी 2010 को कहा था कि भारत के पास उपग्रह को मार गिराने वाली मिसाइल क्षमता है लेकिन वह असली उपग्रह को मार कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं करेगा। भारत इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता क्योंकि इससे अंतरिक्ष में कचरा पैदा होता है। इन कचरों से अंतरिक्ष में उपग्रहों के सिस्टम को नुक़सान पहुँचता है। उस समय डीआरडीओ चीफ़ रहते हुए वी के सारस्वत ने जो कहा मान लिया गया। आज वही नीति आयोग के सदस्य बनकर सारस्वत यूपीए सरकार को निशाना बना रहे हैं। आप इनके बयान को इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की तरह वी के सारस्वत ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

ज़ाहिर है यह राजनीति है। इसरो और रक्षा अनुसंधान का इस्तमाल नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं। उनका राष्ट्र के नाम संबोधन करना और कुछ नहीं बल्कि मतदाताओं को प्रभावित करना था। वे पुलवामा के बाद ऐसा कुछ चाहते थे जिससे पाँच साल की नाकामी पर चर्चा और सवाल ग़ायब हो जाएँ। जो संवाददाता उज्ज्वला योजना की ख़ामियों की रिपोर्टिंग ठीक से नहीं कर पाते वही बुधवार को दिन भर अंतरिक्ष विज्ञान के एक्सपर्ट बन गए। उनकी रिपोर्टिंग में विज्ञान कम था। मोदी का गुणगान था और विपक्ष का उपहास।

सितंबर 2014 से इसरो देश के नाम पर भाजपा और नरेंद्र मोदी की राजनीति का केंद्र बन गया था जब मँगलयान के समय प्रधानमंत्री मोदी खुद वैज्ञानिकों के बीच मौजूद थे। उसी दिन तय हो गया था कि भारत की वैज्ञानिक कामयाबी वैज्ञानिकों की नहीं होगी, प्रधानमंत्री मोदी की होगी। चीन ने भी इस क्षमता का परीक्षण किया मगर उसने टीवी पर आकर दुनिया को नहीं बताया। यही परंपरा रही है। अंतरिक्ष विज्ञान की कामयाबी वैज्ञानिकों पर छोड़ दी जाती है। लेकिन अब यह सब मोदी के लिए प्रोपेगैंडा का हिस्सा भर हैं।

चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की जाँच कर रहा है। आयोग के क़ानूनी सलाहकार रहे मेंदीरत्ता ने द प्रिंट से कहा है कि उन्होंने आचार संहिता लागू होने के बाद किसी प्रधानमंत्री को कभी ऐसा करते नहीं देखा। प्रधानमंत्री ने संबोधन में ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है जिनका इस्तमाल अपने राजनीतिक मंचों पर करते रहे हैं। यह मामला चुनाव आयोग का इम्तिहान है। मुझे संदेह है कि आयोग कुछ करेगा। वह बहाने ढूँढ लाएगा। क्या हम एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग का समापन देख रहे हैं ? समापन का सीधा प्रसारण !

हे राष्ट्र ! उठो, अब तुम इन संस्थाओं को संबोधित करो। बहुत देर हो चुकी है। मृत्यु शैय्या पर पड़ी इन संस्थाओं को कराहते मत देखो।

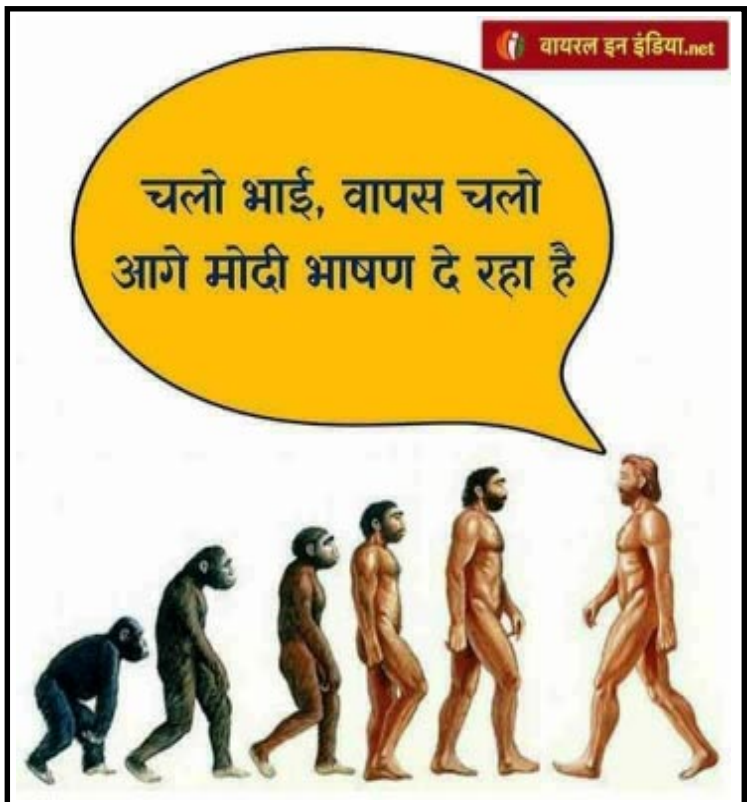

गधे ने बाघ से कहा, घास नीले रंग की होती है; बाघ ने कहा, नहीं घास का रंग हरा है !

दोनों के बीच चर्चा तेज हो गई। चर्चा विवाद का रूप ले ही रही थी कि किसी ने सुझाया, क्यों ना जंगल के राजा से निर्णय करवाते ! दोनों ही अपने-अपने तर्कों पर दृढ़ता से अड़े थे ! इस विवाद को समाप्त करने के लिए, दोनों जंगल के राजा शेर के पास गए !

पशु साम्राज्य के बीच में, सिंहासन पर एक शेर बैठा था !

बाघ के कुछ कहने से पहले ही गधा चिल्लाने लगा, 'महाराज! घास नीला है ना ? शेर ने कहा, हाँ! घास नीली है।' गधा बोला ! ये बाघ नहीं मान रहा! उसे , ठीक से इसकी सजा दी जाए।

राजा ने घोषणा की ! " बाघ को एक साल की जेल होगी" राजा का फैसला गधे ने सुना , और वह पूरे जंगल में खुशी से झूमता फिरे , कि " बाघ को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई " !!

बाघ शेर के पास गया और पूछा, क्यों महाराज ? घास हरी है , क्या यह सही नहीं है ? शेर ने कहा ! हाँ! घास हरी है ! मगर .. तुम को सज़ा ! उस मूर्ख , गधे के साथ बहस करने केलिये दी गई हैं ! !... आप जैसे बहादुर और बुद्धिमान जीव ने गधे से बहस की ! ! !

और निर्णय कराने ,
मेरे पास , चले आये ! ! !

कहानी का सार ? 2019 में अपना वोट सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को दें !
... बस !.. . भक्त गधों से बहस ना करें !

जेटली को आईना दिखाने के लिए काफी है समझौता ब्लास्ट.....

पेज एक का शेष

भी आयोजित किए थे। 2014 में आरएसएस की राजनीतिक विंग भाजपा केंद्र में सरकार में लौटी थी।

इतनी ताकतवर होकर कि धीरे-धीरे लोकतांत्रिक संस्थाएं मोदी सरकार के सामने बौनी और अप्रासंगिक नज़र आने लगीं। तभी ब्लास्ट्स के इन खास केसेज को देख रही एनआईए की भूमिका पर सवाल भी उठने लगे थे। यहां तक कि मालेगांव ब्लास्ट केस की विशेष सरकारी वकील रोहिणी सलायन ने आरोप लगाया था कि सरकार बदलने के बाद एनआईए उन्हें इन मामलों में नरम रुख अख्तियार करने के लिए कह रही है। मुख्य आरोपी संघ से जुड़े रहे थे। केंद्र में संघ की राजनीतिक इकाई की ताकतवर सरकार थी और एनआईए उसके अधीन थी। एनआईए की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता के हश्र को अंततः समझौता एक्सप्रेस केस के फैसले के जज टिप्पणी से भी समझा जा सकता है।

लेकिन, जज अगर अपनी पीड़ा और मजबूरी को बयान करने वाली टिप्पणी नहीं भी करते तो? तो क्या किसी जरा भी समझदार व्यक्ति के लिए देश के मौजूदा हालात को समझना मुश्किल होता? कितने मामले जनता के सामने गुजर चुके हैं। एक जज लोया की मौत को लेकर क्या-क्या बातें सामने आती रही हैं। कितने लोगों को सरेआम मारते-पीटते हुए, नृशंसता से हत्या करते हुए वीडियो बनाए गए और हमलावरों-हत्यारों के जरिये ही वायरल कर दिए गए! क्या जनता वाकिफ नहीं है कि ये कौन लोग हैं, किस विचार, किस संगठन से जुड़े हैं और ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें बचा लेती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बहुसंख्यक जनता ने इस स्थिति को आदर्श स्थिति के लिए स्वीकार कर लिया है।

वह इन्हीं सब के लिए हर मुद्दा-मसला भुलाकर वोट नहीं दे रही है? और क्या विपक्ष ने इसी राजनीति को स्वीकार नहीं किया है? और क्या किसान और क्या सामाजिक न्याय के मसीहाओं ने चुनावी समीकरणों को साधने के इंतजार के अलावा कभी जनता के अमानवीयकरण के अभियान के बरक्स कोई गंभीर मुहिम छेड़ने की कोशिश की? आज इन मसीहाओं की हैसियत अपने वोटर तक को खतरनाक किस्म के प्रायोजित परसेप्शन्स में फंसने से रोकने की नहीं है। हालत तो यह है कि मसीहा खुद उस दरवाजे पर सिर नवाते रहे हैं, कुछ वहीं के होकर रह जाते हैं और कुछ मददगार की भूमिका के वादे के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिशें करते रहते हैं। इन मसीहाओं के विभिन्न जिलों के बहुत से कद्दावर फासिस्टों की चौखट से सिर्फ मौका हासिल करने भर की दूरी पर डोलते दिखाई देते रहते हैं।

समझौता एक्सप्रेस विस्फोट केस में फैसला सुनाने स्पेशल एनआईए कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने उम्मीद के तौर पर पुलिस के उन एएसआई कश्मीर सिंह का उल्लेख किया है जिन्होंने मानवता, साहस और कर्तव्यपरयाणता का परिचय देते हुए जलती ट्रेन से लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। इसी तरह हम कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे बीच उम्मीद के तौर पर हेमंत करकरे या विकास नारायण राय जैसे पुलिस अफसर भी मौजूद रहते हैं जो किसी केस को एक प्रतिबद्ध प्रोफेशनल की तरह डरे बिना तथ्यों और सबूतों के आधार पर इस तरह आगे बढ़ा देते हैं कि उस लाइन को मिटा पाना मुमकिन नहीं रह जाता है। मक्का मस्जिद केस में भी मुस्लिम लड़कों को उठा ही लिया गया था

जिन्हें बाद में छोड़ देना पड़ा। अगर करकरे की जांच की लाइन गलत होती तो क्या उन्हें छोड़ पाना संभव होता? अगर विकास की फाइंडिंग्स गलत होतीं तो मोदी सरकार के दौरान नये या एडिशनल एविडेंसेज केस में न जोड़ दिए गए होते? लेकिन, इस तरह के अफसर कितने हैं? और जो हैं, उन्हें कितने दबावों से गुजरना पड़ता है? मुंबई के आतंकी हमले में शहीद हो गए करकरे पर किस तरह के घिनौने हमले किए जा रहे थे, कौन नहीं जानता? कांग्रेस की साजिश कहकर तथ्यों से मुंह मोड़ना हास्यास्पद है। कांग्रेस की भूमिका तो थी पर इतनी कि यूपीए सरकार के दौरान भी इन केसेज में जो गति अख्तियार की जानी चाहिए थी, उसकी छूट गायब थी। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति में पनाह ढूंढने वाली कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों से किसी करकरे या ऐसे किसी प्रतिबद्ध अफसर को क्या मदद मिल सकती थी? पॉपुलर पॉलिटिक्स की विपक्षी पार्टियों में से किसी की भी कभी ऐसी मंशा तक नहीं रही कि अपने कोर वोटर्स को ही सेक्युलर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना सिखाया जाए।

नाजुक पलों में भी भीतर के इंसान से संचालित होने वाले शख्स इतने नासमझ नहीं होते कि वे किसी दल, किसी नेता या गफलत में डूबे समाज से अपने लिए किसी कवच की उम्मीद करते हों। हम देखते हैं कि इस वक्त में भी कोई एक मामूली पत्रकार किसी क्षण में किसी केस में भय या लालच से प्रभावित होने से इंकार कर देता है और इसकी कीमत चुकाता है। कोई पुलिस अधिकारी अपनी संवैधानिक भूमिका निबाहने के लिए तत्पर हो जाता है और इसकी कीमत चुकाता है। कोई जज अपनी कुर्सी की गरिमा और जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने पिता को कह देता है कि वह ग़लत फैसला देने के बजाय गांव में आकर खेती से गुजारा कर लेना पसंद करेगा।

लेकिन, समझौता एक्सप्रेस केस को लेकर विकास नारायण राय से बात करते हुए उनके आशावाद ने मुझे हैरान किया। वे माहौल की निराशा को स्वीकार करते हैं पर उतना ही जोर देकर कहते हैं कि जनता का बड़ा हिस्सा संविधान विरोधियों के साथ नहीं है। यह एक अलग विषय है कि वह कितना प्रभावी है या उसे कितना संबोधित किया जा पा रहा है। वे कोई नया एक्ट बनाने की जरूरत महसूस करने लगते हैं जबकि मैं सोचता हूं कि एक्ट बनाने वाले तो कोई और ही हैं या जो एक्ट हैं उन्हें ही सिर के बल खड़ा कर दिया गया है।

संवैधानिक मूल्यों पर पाबंद पुलिस अधिकारियों पर सुनियोजित हमलों को लेकर वे चिंता तो जताते हैं पर निराश नहीं होते। कहते हैं कि अफसर को प्रोफेशनली और संवैधानिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। लेकिन, जनता कहां खड़ी है, ऐसे सवाल पर वे दोहराते हैं, मैं नहीं मानता कि पब्लिक देर तक यह अफोर्ड करती रहेगी। लेकिन, विपक्ष जो लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देता रहता है, चुनाव तक में तो एकजुट नहीं हो पा रहा है, इस पर वे कहते हैं कि दुनिया भर में यही सब हो रहा है लेकिन यही होता रहेगा, यह मुमकिन नहीं है।

नदीम के बहाने

हरियाणा में हिसार जिला के बालसमन्द गांव में डेढ़ साल का एक बच्चा 70 फीट गहरे ट्यूबवेल बोर में गिर गया। मां बेर तोड़ रही थी कि बच्चा खेलता डोलता बोर की तरफ चला गया और गिर गया उसमें। ढूंढ़ा गया तो बोर मे से रोने की आवाज आई। मां के प्राण सूख गए। उसने शोर मचाया तो पास में काम करने वाले लोग आए।

सबने नबी को याद किया होगा। क्योंकि बच्चे का नाम नदीम है। कुछ हिन्दू भी आये होंगे। उन्होंने भी अपने-अपने इष्ट को याद किया होगा। कहा होगा आओ, बचाओ इस बच्चे को। हमने बहुत लड़ाईयां लड़ी हैं आपके लिए। हमने बहुत बनाये हैं धार्मिक स्थल आपके लिए। लोगो ने आनन फानन में जिस चीज़ का इंतजाम किया होगा वह धूप बत्ती, नमाज का सामान आदि होगा कि नबी को बुलाया जाए। कृष्ण को बुलाया जाए। बड़े किस्से समाहित हैं धर्मगर्न्थो मे कि ऐसे बचाया द्रोपदी को, ऐसे चांद में क्रैक किया ।

लोगों ने लेकिन यह सब नहीं किया। सबसे पहले रस्सी का इंतजाम किया, उन्होंने फोन निकाला सबसे पहले। प्रशासन को चेताया। सेना को बुलाया गया। बच्चों के डॉक्टर को बुलाया गया। बच्चे को ऑक्सीजन देने का इंतजाम किया गया। बच्चे को बिस्किट फरूटी भेजी गई। 48 घन्टे बच्चा उस बोरवेल मे फसा रहा। 35 लीटर ऑक्सीजन उस 48 घन्टे में भीतर भेजी गई। सेना के हाथ मे जब बच्चा आया तो उसे स्पेशल जैकेट में कवर किया गया। उसका डॉक्टरी मुआयना किया गया। न्यूमोनिया था उसे। बायां फेफड़ा बुरी तरह प्रभावित था। जो एक उम्मीद जिन्दा थी वह फिर से बैठ गयी थी। बच्चा बेहोश था। तुरंत उसे अग्रोहा के हॉस्पिटल रवाना किया गया। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने ट्रैफिक भरे मार्ग पर मात्र 35 मिनट में उसे अग्रोहा पहुंचा दिया। डॉक्टरों का पूरा पैनल लगा दिया गया और 48 घण्टे बाद बच्चे को खतरे से बाहर निकाल लिया गया। मित्रों। हमे ऐसा ही चाहिये। ऐसी व्यवस्था जो हमारे लिए एक्टिव हो और जो हमे इस त्वरित गति से प्रोटेक्ट करे कि हम अपनी आँखों से देख सकें कि जिन मंदिर-मस्जिदों के लिए हम लड़ते रहे दिन-रात वे कभी बचाने नही आए। जो बचाएगा और जो हमारा जीवन आसान करेगा वह विज्ञान और विज्ञान की अवधारणा पर खड़ा तंत्र है।

लेकिन हम बहुत ही नाशुकरे हैं। हमने शुकराना अदा किया तो नबी का, अल्लाह का, ईश्वर का। हमे अपने नबी ईश्वर पर इतना ही भरोसा था तो कुरान खोलते, आयत पढ़ने लगते। गीता खोलते, श्लोक पढ़ने लगते। क्यो सबसे पहले मोबाइल निकाला जेब से। क्यों सबसे पहले ऑक्सीजन भेजी बोरवेल में। ऑक्सीजन तो अल्लाह ईश्वर ने हर जगह दी हुई है। वहां भी भेज ही देता। एक एक पल एक चीज वह काम आयी जो विज्ञान ने सोची कि यह आपका जीवन आसान कर सकती है। यह जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है।

हमने एक बार भी तंत्र का शुक्रिया नही किया, हमने एक बार भी विज्ञान का शुक्रिया नही किया जो हमारे जीवन को आसान कर रही है। हमें दरअसल विज्ञान का महत्व नही सिखाया गया। हमें हर बात में अल्लाह ईश्वर का शुकराना अदा करना और मंदिर मस्जिद के लिए लड़ना सिखाया गया है। ले जाते किसी मंदिर मस्जिद में बोरवेल से निकालने के बाद । हॉस्पिटल क्यो दौड़े।

कभी बन पड़े तो शहर के सरकारी हस्पताल को भी देख आईये। वहां भी थोड़ी सेवा सफाई कर आईये। मंदिर जैसा चकाचक मस्जिद जैसा साफ क्यो नही होना चहिये आपका शहर का हस्पताल। मंदिर के लिए लड़ने वाले, मस्जिद के लिए लड़ने वाले हस्पतालों स्कूलों के लिए जिस दिन लड़ेंगे उस दिन हम अपने आप को नए स्वस्थ और उन्नत मुल्क में पाएंगे। नदीम के लिए तंत्र और लोगो का एकजुट होकर काम करना बताता है कि जहर घोलने वाले कुछ कर लें, बहुत गहरे में समरसता अभी शेष है।

- वीरेंदर भाटिया